प्रेषक.

अर्जुन सिंह, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग—2 देहरादून : दिनांक: मई,2018 विषय— जनपद देहरादून की रेसकोर्स में ट्यूबवैल , पंप हाउस एवं ओवर हैण्ड टेंक के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 558/अप्रै०टी०ए०सी०/203 दिनांक 29 अप्रैल,2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर (नगरीय) के अंतर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या— 850/2015 के अनुपालन में शासनादेश संख्या— 694/उन्तीस(2)/16—2(56पे0)/2016 दिनांक 04 जनवरी, 2017 द्वारा जनपद देहरादून की रेसकोर्स में ट्यूबवेल, पंप हाउस एवं ओवर हैण्ड टैंक का निर्माण से संबंधित कार्यो का विस्तृत प्राक्कलन रू० 239.70 लाख पर विभागीय टी० ए० सी० उपरांत निर्माण कार्य हेतु रू० 125.01 लाख, अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अंतर्गत रू० 77.69 लाख एवं सैन्टेज रू० 34.45 लाख कुल रू० 237.15 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तद्कम में उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018—19 में 40 प्रतिशत की धनराशि रू० 94.86 लाख (रू० चौरानब्बे लाख छयासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम

प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(v) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी एवं कार्यदायी संस्था के रूप में प्रबन्ध निदेशक इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता से कार्य स्थल का निरीक्षण भलीभॉति अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही

उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2017, वित्त नियम कार्य कराया जाय। संग्रहं खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगम नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्टिचत क़िया जाय।

निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला

से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- 01- जलपूर्ति- 101- शहरी जलापूर्ति -03- नगरीय पेयजल- 01- नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण - 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H 1805131312 दिनांक 17 मई,2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 519 / 3—(150)—2017 / XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल,2018 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 82/XXVII (2)/2016

दिनांक 09 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय, (अर्जुन सिंह ) अपर सचिव

पृ0सं0 / २५५ / उन्तीस(2) / 18-2(56पे0) / 2016 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।

2. जिलाधिकारी, देहरादून।

3. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।

4. बजट निदेशालय, देहरादून।

5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-02

6. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।

र्त. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।

8. मीडिया सैन्टर सचिवालय परिसर देहरादून।

9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से, (महावीर सिंह चौहान) संयुक्त सचिव